

प्रेषक

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 06/07/2009

विषय:-नगर निगम, देहरादून के अपुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को राज्य सरकार के पारिवारिक पेंशनर्स के समान दिनांक 01 जुलाई, 2008 से 7% (सात प्रतिशत) की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 408/IV-श0वि0-08-03(न0वि0)/02 दिनांक 12 मई 2008 के द्वारा नगर निगम, देहरादून के पेंशनर्स को राज्य सरकार के सिविल और पारिवारिक पेंशनर्स के समान मंहगाई भत्ते का लाभ प्रदान करते हुए 47 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य की गई थी। चूंकि राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनर्स आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग-7 के कार्यकाल ज्ञाप संख्या 152/XXVII (7)पें0/2007 दिनांक 27मई,2009 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2008 से मंहगाई राहत की 7 प्रतिशत(सात प्रतिशत) की किश्त दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अतः उक्त एवं शहरी विकास विभाग के शासनादेश सं0 408/IV-श0वि0-08-03(न0वि0)/02 दिनांक 12 मई, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, देहरादून के अपुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को भी दिनांक 01 जुलाई, 2008 से मंहगाई राहत की दर 07 प्रतिशत बढ़ाकर अब कुल 54 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- नगर निगम, देहरादून द्वारा अपने अपुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दी जाने वाली पेंशन तथा राहत की कुल धनराशि उस धनराशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा अपने उसी श्रेणी के अपुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन और राहत के रूप में समय समय पर दी जाती है।

3- जिन कर्मचारियों का 1.1.2006 से वेतनमान पुनरीक्षित किया गया है उन्हें पूर्व से राज्य सरकार के कार्मिकों की भांति मंहगाई भत्ता देय है। अतः राज्य सरकार के पेंशनर्स की भांति नगर निगमों के सेवा निवृत्त को मंहगाई राहत अनुमन्य होगी तथा जिन पेंशनर्स की पेंशन पुनरीक्षित नहीं हुई है उन्हें पूर्व दरों के आधार पर निर्गत शासनादेश के आधार पर अनुमन्य होगी।

4- उक्त के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नगर निगम, देहरादून द्वारा अपने अपुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दी जाने वाली मंहगाई राहत में शासन द्वारा कोई अंशदान/अनुदान देय नहीं होगा तथा उक्त भुगतान निगम द्वारा अपने वित्तीय श्रोतों से किया जायेगा।

5- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2453/XXVII(7)/2007, दिनांक 29.9.2009 में प्राप्त उनकी सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

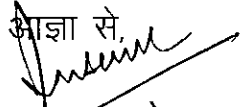
भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या ६१५/IV(1)/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
6. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-7 उत्तराखण्ड देहरादून
- ✓ 7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

 (सुभाष चन्द्र)
 अनु सचिव।